Move for a Moratorium on Nuclear Tests

*383. SHRI CHITTA BASU:

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to initiate a move for a moratorium on all kinds of nuclear tests, over ground, underground or in the air, pending the conclusion of a comprenensive test ban treaty;

(b) if so, whether any Government has since been sounded; and

(c) if so, the names of those Governments and their reaction?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJYAYEE): (a) to (c). Eversince 1954, when India had taken the initiative in regard to the banning of all nuclear weapon tests, the Government of India has consistently and firmly expressed the view that, pending the conclusion of a treaty banning all nuclear weapon tests, there should be an immedrate suspension of all kinds of nuclear weapon tests in all environments by all States. Most recently, at the Special Session of the UN General Assembly devoted to disarmament, which was held in New York in May-June, 1978, India had reiterated this position of principle and had also tabled a draft resolution (text attached). However, since it was generally agreed that the Special Session should adopt one single and comprehensive Final Document by consensus and not vote on separate resolutions, India decided not to press its draft resolution to a vote at that session. At the same time, India was able to get the idea of suspension of nuclear weapon tests included in the Final Document which states, *inter alia*, that "various views were expressed by non-nuclear weapon States that, pending the conclusion of this treaty, the world community would be encouraged if all the nuclear-weapon States refrained from testing nuclear weapons."

DRAFT RESOLUTIONS

UNITED NATIONS
GENERAL ASSEMBLY

A/S-10/AC. 1/L. 10
23rd June, 1978.
ORIGINAL: *ENGLISH*

Tenth special session

AD HOC COMMITTEE OF THE *TENTH SPECIAL SESSION*
Agenda item 9

Review and appraisal of the present International situation in the Light of the pressing need to achieve substantial progress in the field of disarmament, the continuation of the arms race and the close inter-relationship between disarmament, international peace and security and economic development

India: Draft Resolution
Urgent need for cessation of further testing of nuclear weapons

The General Assembly,

Gravely concerned that continued testing of nuclear weapons exacerbates the arms race, poses a serious danger to the environment and constitutes a grave hazard to the health of present and future generations of mankind.

Recalling its resolutions on the question of nuclear weapon testing which have been adopted each year ever since 1958 and which, *inter alia*, have condemned all nuclear-weapon tests,

Reaffrming that a comprehensive test ban is a matter of the highest priority,

Noting the statements that comprehensive test-ban treaty is nearing finalization,

Calls upon all nuclear-weapon States, pending the conclusion of a comprehensive test-ban treaty, to reafrain from conducting any further testing of nuclear weapons

पांडिचेरी में प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय

3539 श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय के बारे में 6 अप्रैल 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकार ने वर्ष 1974-75 में पांडिचेरी में प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय 38 रुपये 84 पैसे किया था और यदि हां, तो क्या 1976-77 और 1977-78 में इसको बढ़ाने का विचार था ,

(ख) यदि हां, तो कितना तथा, क्या सरकार अब तक किए गए प्रति व्यक्ति व्यय से सन्तुष्ट है , और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य देशों से सहायता लेने के पक्ष में है और यदि हां, तो इस समय इस सम्बंध में किन-किन देशों के साथ बातचीत चल रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) प्रति व्यक्ति व्यय 38 84 रुपये का जो कि राज्य और केन्द्र, दोनों सरकारों द्वारा किये गये प्लान और नान-प्लान खर्च पर आधारित है । 1975-76 में पांडिचेरी स्वास्थ्य सबंधी प्रति व्यक्ति खर्च जो 50 04 रुपये हुआ था, वह 1976-77 मे घटकर 49 42 रुपये हो गया । वर्ष 1977-78 के खर्च के आकडे अभी सकलित किए जाते हैं ।

केन्द्र और राज्य सरकारें पांडिचेरी में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं और राज्य सरकार को राज्य और केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय के अनुसार सहायता दी जा रही है ।

1976-77 में पांडिचेरी में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर जो योजना खर्च 28 11 लाख रुपये हुआ था, वह 1977-78 में बढ़कर 30 28 लाख रुपये हो गया ।

(ग) सरकार किसी भी राज्य विशेष के लिए विदेशी सहायता नही माग रही है । वैसे, विदेशो ने मलेरिया नियत्रण, अधता निवारण, चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देने आदि जैसी हमारी कुछेक राष्ट्रीय योजनाओ के लिए सहायता दी है । किसी राज्य विशष के स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए निश्चित किए गये समग्र योजना परिव्यय में सारे देशगत और विदेशी राज सामान, दानो की झलक मिलती है ।

जूनागढ़ में डाकघर भवन की कीमत

3540 श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उस डाकघर भवन की अन्तिम कीमत क बारे में जानकारी दे दी है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ शहर मे है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी कीमत बताई गई है और यदि नहीं, तो इसके लिय सरकार ने कब और किस प्रकार के स्मरणपत्र गुजरात सरकार को इस बारे मे भेजे हैं ,

(ग) क्या इस भवन के लिये कोई कीमत निर्धारित की गई थी और यदि हां, तो कब और कितनी और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ,

(घ) क्या जूनागढ़ के आजाद चौक में स्थित डाकघर में सुविधाओ म वृद्धि करने के लिये कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर प्रस्तावित व्यय का योजनावार ब्यौरा क्या है और

(ङ) जूनागढ़ के इस डाकघर के भवन में सुधार करने के लिये क्या योजनाये बनाई गई हैं और वहां डाकघर सुविधाओ में वृद्धि करने के लिये क्या योजनायें बनाई गई है और इन योजनाओ को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) (क) और (ख) जी हां । फरवरी 1978 में इस इमारत का मूल्य 3,00,200 रु० सूचित किया गया था ।

(ग) डाकतार सिविल इन्जीनियरी विंग ने इस सपत्ति का मूल्य 97,800/-रु० आका था । इस सपत्ति का हस्तातरण डाकतार विभाग को कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) जूनागढ़ मुख्य डाकघर की मौजूदा इमारत में सभी डाक सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ङ) इस समय यह इमारत राज्य सरकार के अधिकार में है । इमारत में कुछ सुधार करने के लिये राज्य सरकार को लिखा गया है ।